17

अध्याय

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी

- वर्ष 2014–15 में, कोयला मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। एनआईसी के साथ निकटतापूर्वक कार्य करते हुए, मंत्रालय ने डिजीटल सेवाओं की क्षमता को काफी संवर्धित किया है, ई–सेवा सुपुर्दगी के लिए ई–अवसंरचना में विस्तार किया है तथा मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश संविर्धित करने तथा ई–कौशल का विकास करने के लिए कार्य किया है।
- मंत्रालय में नेशनल इनफॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) द्वारा गठित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कंप्यूटर केन्द्र कार्यरत है जो कि तकनीकी आईसीटी परामर्शदायिता, सॉफ्टवेयर विकास, प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन, वेब सेवाएं, नेटवर्किंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एवं ई–मेल, डाटाबेस प्रबंधन एवं सुरक्षा की व्यवस्था के लिए प्रणालियों से सुसज्जित है।
- श्री पीयूष गोयल, माननीय कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 20 जनवरी, 2015 को मंत्रालय के लिए पुर्नअभिकल्पित नई वेबसाइट http://coal.nic.in; लांच की गई थी। यह वेबसाइट खुले स्रोत दरुपल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए आंतरिक रूप से विकसित की गई थी जो कि वेब 2.0 मानकों के अनुरूप है तथा जीआईजीडब्ल्यू अनुकूल है। इसका अभिकल्पन विकास तथा रख–रखाव एनआईसी द्वारा किया गया है।
- मंत्रालय में कोल प्रोजेक्ट मानीटरिंग पोर्टल कार्यान्वित किया गया है। यह व्यापक एमआईस है जो कोयला क्षेत्र के सभी मुख्य उद्योग, कोयला कंपनियां, सीआईएल, एनएलसी, मंत्रालयों, राज्यों तथा कोयला मंत्रायल को लिंक करता है। विभिन्न राज्यों/मंत्रालयों/विभागों में लंबित मुद्दों वाली कोयला परियोजनाओं को इस प्रणाली पर प्रस्तुत किया जाता है तथा इस मंच पर इन पर गहन अनुवीक्षण तथा चर्चा तथा समाधान किया जाता है जिससे संचयी सूचना प्राप्त करने से संबंधित कठिनाइयां तथा निर्णय लेने में विलंब समाप्त होता है।
- मंत्रालय ने कोयला ब्लॉकों तथा कोयला लिंकेज के अनुवीक्षण के लिए वेब आधारित व्यापक एकीकृत प्रणाली का विकास शुरू किया है। कार्य आधारित तथा भूमिका अधारित प्रणाली सभी स्टेकधारकों को एक मंच प्रदान करेगी ताकि ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जा सके।
- कोयला उद्योग के यूजर के लिए अनापत्तियां/अनुमतियों के लिए ऑनलाइन प्रणालियों का विकास किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, अपने आवेदनों की स्थिति का पता लगाने तथा ऑनलाइन अनुमोदनों/अनापत्तियां प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा सके।
- केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से मंत्रालय कोयला ब्लॉकों का आबंटन कर रहा है। ऑन लाइन ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी का उपयोग करते हुए उन कोयला खानों का पुर्नआबंटन किया जा रहा है जिनका आबंटन रद्द कर दिया गया था। पोर्टल के माध्यम से आन लाइन बोली शुरू हो गई है।
- मंत्रालय ने सक्षमतः एवं पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए अपने कार्यसंचालन में आफिस आटोमेशन एप्लिकेशन को अपनाया है। इनमें से कुछ हैं:– ई–ऑफिस जिसमें ई–लीव, ई–नोटिस बोर्ड, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम(केएमएस) तथा ई–टूर शामिल हैं। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (एफटीएस) फाइलों को प्राप्त तथा प्रस्तुत करने के लिए। आकस्मिक बिलों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए ई–बिल प्रणाली, पे–रोल के लिए काम्प्रिहेंसिव डीडीओ, वेतन पर्ची, आयकर विवरण तथा जीपीएफ विवरण को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए इंट्रा–कोल डैश बोर्ड। मंत्रालय में ई–फाइल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। मंत्रालय ने तत्काल संदर्भ तथा सरल उपलब्धता के लिए फाइलों को डिजीटल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक मंत्रालयों की 4500 फाइलों एवं रिकार्डों सहित लगभग 6 लाख पृष्ठों को डिजीटल बनाया जा चुका है।
- मंत्रालय में ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन का कार्यान्वयन किया गया है तथा इसका सक्रियता से प्रयोग किया जा रहा है। इनमें आरटीआई मामलों के प्रबंध के लिए आरटीआई एमआईएस, एसीसी रिक्तियों के अनुवीक्षण के लिए एवीएमएस, लोक शिकायत, संसदीय प्रश्न तथा पूरक एमआईएस, न्यायालय के विचाराधीन मामलों के अनुवीक्षण के लिए सीपीजीआरएमएस शामिल हैं।

- मंत्रालय ने समय की बचत के लिए तथा कागजों की लेनदेन में कमी करने के लिए एनआईसी ई–मेल पर इंट्रा मिनिस्ट्री तथा इंटर मिनिस्ट्री सरकारी संप्रेषण शुरू किया है। मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालय/विभागों को भेजी जाने वाली सभी नियमित बाहय रिपोर्टें इस मंत्रालय की वेबसाईट पर दर्शायी जाती हैं।
- संपर्क पोर्टल पर लगभग 3.57 लाख कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों तथा ई–मेल सहित एक डाटा बैंक स्थापित किया गया है।
- विभिन्न भवनों में तैनात कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के लिए मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कार्यान्वित की गई है।